सकल जीएसटी संग्रह जून में 13.9% बढ़ा

जीएसटी संग्रह में महंगे आयात का काफी योगदान रहा

तिमाही में कुल 91,482 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया.

नई दिल्ली, 01 जुलाई. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सकल राजस्व संग्रह जून में 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1,94,812 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस मजबूत जीएसटी संग्रह में महंगे आयात का काफी योगदान रहा मूल्य के आधार पर आयात बढ़ने से आयात पर जीएसटी से प्राप्त राशि 34.6 प्रतिशत बढ़कर 60,038 करोड़ रुपये हो गया.

घरेलू लेन-देन पर जीएसटी राजस्व 1,34,774 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल जून की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक है. वित्त मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में कुल 32,436 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया. इस प्रकार, शुद्ध जीएसटी संग्रह 11.2 प्रतिशत बढ़ा और जून में 1,62,377 करोड़ रुपये रहा.

घरेलू कारोबारियों को बीते महीने 17,767 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया. यह सालाना 42.9 प्रतिशत अधिक है. आयातकों को जारी किया गया रिफंड 15.6 प्रतिशत बढ़कर 14,669 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान जीएसटी संग्रह 8.4 फीसदी बढ़कर 6,31,699 करोड़ रुपये रहा. तिमाही में कुल 91,482 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया. यह एक साल पहले के मुकाबले 16.8 प्रतिशत अधिक है. इस प्रकार, तिमाही का शुद्ध राजस्व संग्रह 7.1 प्रतिशत बढ़कर 5,40,218 करोड़ रुपये हो गया.

बंपर उछाल- जून महीने का सरकारी खजाना शानदार जीएसटी वसूली से भर गया है, जिसमें घरेलू लेनदेन और आयात दोनों से राजस्व में भारी वृद्धि दर्ज की गई है. नए स्लैब: अब मुख्य रूप से 5प्रतिशत (आवश्यक और घरेलू सामान) और 18प्रतिशत (अधिकांश उपभोक्ता उत्पाद और सेवाएं) के दो मुख्य स्लैब काम कर रहे हैं. **सरलीकृत संरचना-** अब 12प्रतिशत और 28प्रतिशत के पुराने टैक्स स्लैब को ज्यादातर खत्म कर दिया गया है.

वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कमजोर मानसून

नई दिल्ली, 01 जुलाई. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने पश्चिम एशिया संकट के बीच कमजोर मानसून और ऊर्जा बाजार की अनिश्चितता के पर चिंता व्यक्त की है. विभाग की ओर से मंगलवार को जारी जून की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था मजूबत है और पश्चिम एशिया संकट के बीच भी अधिकतर आर्थिक संकेतक मजबूत बने हुए हैं, हालांकि कुछ संकेतकों में हल्की कमजोरी देखी गयी।इसमें कहा गया है, जलाशयों के अच्छे स्तर और पर्याप्त उर्वरक उपलब्धता के कारण कृषि गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां जारी हैं , हालांकि दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमजोर प्रगति ने खरीफ बुवाई पर दबाव डाला है और मानसूनी बारिश की कमी चिंता का विषय है.

फास्टैग एनुअल पास का बढ़ा इस्तेमाल

अब 19 प्रतिशत टोल ट्रैफिक इसी से गुजर रहा

नई दिल्ली, 01 जुलाई. देशभर में हाईवे पर फास्टैग एनुअल पास का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, अब कुल टोल पास ट्रैफिक में 19 प्रतिशत हिस्सेदारी फास्टैग एनुअल पास की हो गई है. यह पिछले छह महीनों में करीब 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, क्योंकि दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा लगभग 13 प्रतिशत था.

आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में देशभर के टोल प्लाजा से कुल 44.4 करोड़ वाहन यात्राएं दर्ज की गईं। इनमें से 8.4 करोड़ यात्राएं एनुअल पास के जरिए हुईं।बाकी 36 करोड़ यात्राओं से टोल कलेक्शन के जरिए कुल 7,214 करोड़ रुपये की वसूली

हुई. तुलना करें तो जून 2025 में फास्टैग के जरिए 38.6 करोड़ ट्रिप्स दर्ज हुई थीं, जिससे 6,973 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ था. इस तरह एक साल में ट्रिप्स की संख्या में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन राजस्व वृद्धि केवल 3.5 प्रतिशत रही. इसकी मुख्य वजह एनुअल पास के बढ़ते इस्तेमाल को माना जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, एनुअल पास की वजह से टोल कलेक्शन पर कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत का असर पड़ा है.

यह फास्टैग एनुअल पास 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 3,075 रुपये रखी गई. इसके तहत वाहन चालक एक साल में 200 हाईवे ट्रिप्स कर सकते हैं।यानि प्रति यात्रा खर्च लगभग 15.40 रुपये पड़ता है, जो सामान्य टोल शुल्क की तुलना में काफी कम है।यह सुविधा फिलहाल सिर्फ निजी यात्री वाहनों के लिए उपलब्ध है, जो देश के कुल टोल ट्रैफिक का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं. वहीं टोल से होने वाले कुल राजस्व में इनकी हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है।दूसरी तरफ ट्रक, बस और वैन जैसे व्यावसायिक वाहनों को सामान्य दरों पर अधिक टोल शुल्क देना पड़ता है.

वाहन की बिक्री जून में भी रही जबरदस्त

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री 23.78 प्रतिशत बढ़ा

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 183 फीसदी बढ़कर 14,800 इकाई पर

नई दिल्ली, 01 जुलाई. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पिछले साल सितंबर में किये गये सुधारों के बाद से वाहन उद्योग में आयी तेजी इस साल जून में भी जारी रही. देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता मारुति सुजुकी ने बुधवार को बताया कि जून में उसकी कुल बिक्री 19.28 फीसदी बढ़कर दो लाख 390 इकाई पर पहुंच गयी.

इसमें घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री 23.78 प्रतिशत और निर्यात 11.90 फीसदी बढ़ा. कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,47,187 यात्री वाहन बेचे. उसका निर्यात 42,768 इकाई रहा. दूसरी सबसे बड़ी यात्री वाहन कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने जून में घरेलू बाजार में 62,076 यात्री वाहन बेचे और 1,007 वाहनों का निर्यात किया. कुल बिक्री 63,083 इकाई रही जो एक साल पहले के मुकाबले 69 फीसदी अधिक है. कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 183 फीसदी बढ़कर 14,800 इकाई पर पहुंच गयी. महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री जून 2025 की तुलना में 37 प्रतिशत बढ़कर 1,06,207 इकाई दर्ज की गयी.

दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की फैक्टरी गेट से बिक्री 5,41,159 इकाई रही. यह एक साल पहले के 5,53,963 वाहनों की तुलना में कम है. इसमें घरेलू बिक्री में 4.24 प्रतिशत कमी आयी है जबकि निर्यात 32.75 प्रतिशत बढ़ा है. घरेलू बिक्री 5,02,890 इकाई और निर्यात 38,269 इकाई पर रहा. दुपहिया वाहन निर्माता होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की घरेलू बिक्री जून में 4,68,956 इकाई और निर्यात 59,325 इकाई रहा. यह क्रमश: 21 प्रतिशत और 47 प्रतिशत की सालाना बढ़त है. कुल बिक्री 23 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,28,281 इकाई रही.

2026 में परिचालन के क्षेत्र में दर्ज की उल्लेखनीय उपलब्धियां

माल परिवहन से मंडल ने 606.43 करोड़ रुपये का राजस्व किया अर्जित

अहमदाबाद, 01 जुलाई. समयपालन में उल्लेखनीय सुधार- जून 2026 के दौरान मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों की 94.69 प्रतिशत समयपालन उपलब्धि दर्ज की गई, जो जून 2025 की तुलना में 2.95 प्रतिशत बेहतर है.

गांधीधाम क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियां-गांधीधाम क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 2252.93 वैगनों का माल लदान किया गया, जो जून 2025 की तुलना में 12.54 प्रतिशत अधिक है।गांधीधाम क्षेत्र के मुंद्रा पोर्ट से जून 2026 में 587 डबल स्टैक कंटेनर रेक का लदान कर अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड स्थापित किया गया. यह अक्टूबर 2025 में बने 570 रेक के पूर्व रिकॉर्ड से अधिक है. माल लदान एवं राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि-जून 2026 के दौरान अहमदाबाद मंडल ने प्रतिदिन औसतन 2941.8 वैगनों का माल लदान किया, जो जून 2025 की तुलना में 6.83 प्रतिशत अधिक है।इसी अवधि में कुल 4.42 मिलियन टन माल का परिवहन किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 10.21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. कोयले के लदान में 61.36 प्रतिशत, उर्वरकों के लदान में 44.96 प्रतिशत तथा नमक के लदान में 25.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. परिचालन दक्षता में निरंतर सुधार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपयोग में 3.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे परिचालन क्षमता में सुधार हुआ. जून 2026 में 156 लॉन्ग-हॉल मालगाड़ियों का संचालन किया गया, जो पिछले वर्ष के 28 की तुलना में 457.14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है.

यात्रियों की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों में 333 अतिरिक्त कोच लगाए गए तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में 9 अतिरिक्त पार्सल वैन भी जोड़ी गईं।जून 2026 के दौरान पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने परिचालन, माल परिवहन, समयपालन एवं यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं. मंडल भविष्य में भी सुरक्षित, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रेल सेवाएं प्रदान करने तथा परिचालन उत्कृष्टता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है.

शेयर बाजारों में आई मजबूती

444 अंक पर चढ़ा सेंसेक्स

140 अंक पर आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 01 जुलाई. विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 443.97 अंक (0.58 प्रतिशत) की बढ़त में 76,922.64 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 140.10 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की मजबूती के साथ 24,005.85 अंक पर पहुंच गया. दोनों प्रमुख सूचकांक मंगलवार को एक सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए थे।वृहत बाजार में भी लिवाली का जोर रहा. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.69 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.36 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. एफएमसीजी, रियल्टी, मीडिया, ऑटो, बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों के सूचकांक ऊपर बंद हुए. आईटी, धातु, फार्मा, स्वास्थ्य और रसायन समूहों के सूचकांक नीचे रहे. सेंसेक्स की कंपनियों में इटरनल का शेयर सबसे अधिक पौने पांच प्रतिशत चढ़ा. एशियन पेंट्स तथा हिंदुस्तान यूनीलिवर में तीन प्रतिशत और अडानी पोर्ट्स में दो प्रतिशत से ज्यादा की तेजी रही.

बाहरी चुनौतियों के बावजूद देश के बैंकिंग तंत्र की मजबूती कायम

मुंबई, 01 जुलाई. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि बाहरी झटकों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है.

केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्राक्कथन में श्री मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी झटकों का सामना करने के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती दिखायी है. मजबूत आर्थिक विकास, निम्न मुद्रास्फीति, वित्तीय एवं गैर-वित्तीय संस्थाओं की मजबूत बैलेंस शीट तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों ने व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है. उन्होंने कहा कि आरबीआई विकसित हो रहे बाहरी एवं घरेलू जोखिमों के प्रति सतर्क हैं और अपनी अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली को संभावित झटकों से सुरक्षित रखने वाले सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

उद्योगपतियों के साथ वित्तमंत्री की होगी बैठक

सीतारमण फ्रांस की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली, 01 जुलाई. केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई, जहां वह कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी.

वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सीतारमण की इस यात्रा का उद्देश्य भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करना है. फ्रांस में वित्त मंत्री के प्रवास के दौरान भारत-फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय डॉयलॉग- (ईएफडी) आयोजित किया जा रहा है जो उनकी इस यात्रा का एक प्रमुख कार्यक्रम होगा. ऐक्स-आं-प्रोवांस में आयोजित किये जाने वाले यह कार्यक्रम श्रीमती सीतारमण और फ्रांस के आर्थिक, वित्त तथा औद्योगिक एवं ऊर्जा मंत्री रोलां लेस्क्यूर की संयुक्त अध्यक्षता में होगा. इस दौरान दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे तथा भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे.

इंडिगो ने पेश किया लाइट फेयर

नई दिल्ली, 01 जुलाई. देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने बुधवार को अपने इकोनॉमी श्रेणी के ग्राहकों के लिए इंडिगो लाइट फेयर नाम से किराये का एक नया विकल्प पेश किया, जिसमें चेक-इन बैगेज के बिना यात्रा करने पर किराया कम हो जायेगा.

एयरलाइंस ने बताया गया है कि यह एंट्री-लेवल किराया उन यात्रियों के लिए है, जो केवल केबिन बैगेज के साथ यात्रा करते हैं और केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहते हैं, जिनका वे वास्तव में उपयोग करते हैं.

समाचार विशेष

राजनीति और अकाल तख्त के बीच टकराव

मुख्यमंत्री और सिख विधायकों को दिया 30 दिन का समय; मची खलबली

चंडीगढ़. पंजाब की राजनीति और सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच टकराव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है. धार्मिक अपमान विरोधी कानून को लेकर बढ़े विवाद के बीच अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत राज्य विधानसभा की सभी 117 सीटों में से 78 सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया.

अमृतसर में हुई सुनवाई के दौरान अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को कानून में संशोधन कर आपत्तिजनक प्रावधानों को हटाने के लिए एक महीने का समय दिया है. अकाल तख्त का कहना है कि यह कानून बिना पर्याप्त धार्मिक परामर्श के लाया गया, जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं. वहीं, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अकाल तख्त की ओर से भेजे जाने वाले सुझावों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है और आगामी चुनावों से पहले धार्मिक और राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है.

क्या है पूरा मामला?- अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने जगतग गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2026 पर आपत्ती जताते हुए कहा कि इसे सिख समुदाय के बिना परामर्श के ही लागु कर दिया गया है. तो वहीं अकाल तख्त ने पंजाब सरकार से कहा था कि पंजाब सरकर अपने इस कानून से उन प्रावधानों को हटाए जो 'गुरु ग्रंथ साहिब' और सिख समुदाय की भावनाओं के ठेस पहुंचाती हैं.

सरकार एक महिने में संशोधन लाए

दरअसल गड़गज ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि भगवंत मान की सरकार एक महिने के अंदर कानून में संशोधन लाने पर ध्यान दे. अकाल तख्त की आपत्तियों का समाधान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक प्रक्रियाओं में बाधा ना डाले. इतना ही उन्होंने इस मामलों में राज्य के विधायकों को दर्ज आपत्तियों की एक सूची प्रदान किया और 'बीर' शब्द को 'सरूप' में शब्द में बदलने की बात लिखी थी.

जयराम महतो की कुछ अलग करने की कोशिश

झारखंड की राजनीति में चला सवर्ण मोर्चा का दांव

धनबाद. झारखंड में नई तरह की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो सचमुच कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. वह सवर्ण समाज को साधने में जुटे हैं.

दरअसल, राजनीति में राजनीतिक दल ओबीसी, एसटी-एससी, महिला, अल्पसंख्यक आदि वर्गों के नाम पर अलग-अलग मंच और मोर्चों के माध्यम से राजनीति करते हैं. लगभग सभी प्रमुख दलों-भाजपा, कांग्रेस, झामुमो आदि-ने ओबीसी, महिला, युवा और अल्पसंख्यक मंच या मोर्चा बना रखा है. हालांकि, प्रमुख दलों के संगठनात्मक ढांचे में स्वर्ण मोर्चा नहीं है.

डिंपल चौबे स्वर्ण मोर्चा महिला अध्यक्ष

वहीं, डिंपल चौबे को केंद्रीय स्वर्ण मोर्चा महिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी नेतृत्व ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने, संगठन को मजबूत बनाने तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया है. नवनियुक्त पदाधिकारियों ने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया.

अभिनेता राघव लॉरेंस ने राजनीति में रखा कदम

चेन्नई. अभिनेता राघव लॉरेंस ने साफ किया है कि उन्होंने राजनीति में आने का मन तो बना लिया है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह किस पार्टी में शामिल होंगे.

उन्होंने जल्द ही इस बारे में बताने की बात कही है. उनकी राजनीति में आने को लेकर चल रही तमाम अटकलों के बीच उन्होंने यह जानकारी दी है.

उपचुनाव लड़ने को लेकर अपने एक वीडियो मैसेज में राघव ने कहा, आज राजनीति में आकर तुरंत विधायक बनना धर्म नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है विजय ने पहले ही किसी को उस सीट के लिए चुन लिया हो या फिर यह सीट किसी वफादार टीवीके कार्यकर्ता को दी जा सकती है.

राघव ने बताया कि उन्होंने दिव्यांग लोगों के साथ 20 साल से ज्यादा समय तक काम किया है. उन्होंने साफ किया कि सामाजिक सेवा के प्रति उनकी लगन पहले जैसी ही बनी हुई है और इसमें कोई कमी नहीं आएगी.

विशेष | राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बीजेपी से लेकर मायावती सब खेल रहे दांव

सबको क्यों चाहिए टीम डी का सपोर्ट

लखनऊ. देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सक्रिय राजनीतिक दलों ने वोटों का गुणा गणित लगाना शुरू कर दिया है. इसके लिए सभी पार्टियां सबसे पहले संगठन स्तर पर बदलाव करती दिख रही है.

संगठन स्तर पर कांग्रेसए बीजेपीए सपा और बसपा में हालिया लिए गए फैसलों पर नजर डालें तो एक बात कॉमन दिखती है. चारों पार्टियों का 2027 के रण में दलित वाटबैंक पर विशेष फोकस दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल यूपी चुनाव 2027 में टीम डी के ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पाले में करना चाहती है.

राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद विधानसभा चुनाव में भी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के फॉर्मूल पर चलती दिख रही है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में संगठन स्तर पर दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाई है. पार्टी ने जानबूझकर जिला संगठनों, फ्रंटल यूनिट्स और कैंडिडेट चुनने में दलितों और बहुत पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी को बढ़ाया है. साथ ही अपने पारंपरिक मुस्लिम.यादव सपोर्ट बेस से आगे भी बढ़ाया है. इस स्ट्रैटेजी का फायदा 2024 के लोकसभा चुनावों में मिला, जब सपा ने उत्तर प्रदेश की 17 अनुसूचित जाति.आरक्षित संसदीय सीटों में से सात जीतीं. तब से पार्टी ने लगातार पिछड़े और दलित समुदायों से पदाधिकारी बनाए हैं. 2027 के लिए अपने कैंपेन में जाति जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय को मुख्य विषय बनाया है.

कांग्रेस ने दलित नेता को ही प्रभारी बना डाला- संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिख सकता है. ऐसे में कांग्रेस ने भी दलित वोटबैंक पर नजर गढ़ाए दिख रही है. इसके लिए कांग्रेस ने दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को ही यूपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया है. राजेंद्र पाल गौतम को एक अनुभवी संगठन का नेता माना जाता है. कांग्रेस को उनसे उम्मीद है कि वे 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को लीड करेंगे और साथ ही अनुसूचित जातियों के बीच अपनी पहुंच को मजबूत करेंगे.

बीजेपी ने भी दलितों को दी ठीक-ठाक इज्जत

सत्ताधारी बीजेपी ने भी यूपी चुनाव 2027 को देखते हुए संगठनात्मक बदलाव किए हैं. 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने अपनी उत्तर प्रदेश यूनिट के सभी छह रीजनल प्रेसिडेंट को बदल दिया, जबकि 19 वाइस.प्रेसिडेंटए आठ जनरल सेक्रेटरी और कई नए ऑफिस बेयरर अपॉइंट किए, जिसमें जाति के रिप्रेजेंटेशन और रीजनल उम्मीदों के बीच सावधानी से बैलेंस बनाया गया. ये छह रीजनल चीफखुद बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं.